प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): अध्यक्षा जी, जिस धैर्य के साथ आपने सदन का संचालन किया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह अविश्वास प्रस्ताव एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण शक्ति का परिचायक है। भले टीडीपी के माध्यम से प्रस्ताव आया हो, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए कुछ माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बातें कही हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने प्रस्ताव का विरोध करते हुए बात कही है। मैं भी आप सभी से आग्रह करूंगा कि हम सब इस प्रस्ताव को खारिज करें और हम सब तीस साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत के साथ बनी हुई सरकार को, जिसने तेज गति से काम किया है, उस पर फिर से एक बार विश्‍वास प्रकट करें। वैसे मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा मौका है कि हमें अपनी बात कहने का मौका तो मिल ही रहा है, लेकिन देश को यह भी चेहरा देखने को मिला है कि कैसी नकारात्मकता है, कैसा विकास के प्रति विरोध का भाव है।

कैसे नकारात्मक राजनीति ने कुछ लोगों को घेरकर रखा हुआ है और उन सबका चेहरा निखरकर, सज-धजकर बाहर आया है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों? न संख्या है, न सदन में बहुमत है, फिर भी इस प्रस्ताव को सदन में क्यों लाया गया? सरकार को गिराने का इतना ही उतावलापन था, तो मैं हैरान था, सोच रहा था कि इसको 48 घंटे रोक दिया जाए। इस पर जल्दी चर्चा की जरूरत नहीं है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर जल्दी चर्चा नहीं होगी, तो क्या आसमान फट जाएगा, भूकम्प आ जाएगा क्या? अगर चर्चा की तैयारी नहीं थी, 48 घंटे और देर कर दी जाती, तो फिर यह क्यों लाए? इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको टालने की जो कोशिश हो रही थी, वह भी इस बात को बताती है कि उनकी कठिनाई क्या है।

न मांझी, न रहबर, न हक़ में हवाएँ,
है कश्ती भी जर्ज़र, यह कैसा सफ़र है?

मैं जो भाषा सुन रहा था, जो व्यवहार देख रहा था, मैं नहीं मानता हूँ कि यह कोई अज्ञानतावश हुआ है और न ही यह झूठे आत्मविश्वास के कारण हुआ है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि अहंकार इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए खींचकर ले जा रहा है। मोदी हटाओ,

...(व्यवधान) मैं हैरान हूँ, आज सुबह तो चर्चा प्रारम्भ ही हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय-पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी यहाँ पहुँचने के लिए जिनका उत्साह है, कहते हैं, उठो! उठो! लेकिन, यहाँ से न कोई उठा सकता है, न बैठा सकता है, केवल सवा सौ करोड़ देशवासी ही यहाँ पर बैठा सकते हैं और सवा सौ करोड़ देशवासी ही यहाँ से उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पर भरोसा होना चाहिए। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है?

यह अहंकार ही है, जो कहता है कि हम खड़े होंगे, तो प्रधान मंत्री 15 मिनट तक भी खड़े नहीं हो पाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं खड़ा भी हूँ और हमने चार साल तक जो काम किये हैं, उस पर अड़ा भी हूँ। हमारी सोच उनसे अलग है। हमने सीखा है-

सार-सार को गहि रहे,
थोथा देइ उड़ाय।

खैर, मैं सार ग्रहण करने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह आज मुझे मिला नहीं। डंके की चोट पर अहंकार यह कहलाता है कि वर्ष 2019 में पावर में नहीं आने देंगे। जो लोगों में विश्वास नहीं करते और खुद को ही भाग्य विधाता मानते हैं, उनके मुंह से ऐसे ही शब्द निकलते हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन भाग्य विधाता होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा होना जरूरी है। अगर वर्ष 2019 में कांग्रेस सब से बड़ा दल बनती है, तो मैं प्रधान मंत्री बनूंगा, लेकिन दूसरों की जो ढेर सारी ख्वाहिशें हैं, उनका क्या होगा, इस बारे में कंफ्यूजन है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया जी, यह सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। यह तो कांग्रेस का अपने तथाकथित साथियों का फ्लोर टेस्ट है। मैं ही प्रधान मंत्री बनूंगा, के सपने पर और दल भी थोड़ी मोहर लगा दें, इसके लिए ट्रायल चल रहा है। ...(व्यवधान) इस प्रस्ताव के बहाने अपने कुनबे को जो जमाने की कोशिश की है, वह कहीं बिखर न जाए, इसकी चिंता पड़ी है। एक मोदी को हटाने के लिए, जिसे कभी देखने का संबंध नहीं है, मिलने का संबंध नहीं है, ऐसी धुरियों को इकट्ठा करने का प्रयास हो रहा है। मेरी कांग्रेस के साथियों को सलाह है कि जब भी आपको अपने संभवित साथियों की परीक्षा लेनी हो, तो आप जरूर लीजिए, लेकिन कम से कम अविश्वास के प्रस्ताव का बहाना तो

न बनाइए। जितना अविश्वास आप सरकार पर करते हैं, कम से कम उतना विश्वास अपने संभावित साथियों पर तो कीजिए।

अध्यक्ष महोदया जी, हम यहां इसलिए हैं, क्योंकि हमारे पास संख्या बल है। हम यहां इसलिए हैं, क्योंकि सवा सौ करोड़ देशवासियों का हमें आर्शीवाद प्राप्त है। …(व्यवधान) अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिए देश के मन पर, देशवासियों द्वारा दिए आशीर्वाद पर कम से कम अविश्वास न करें। …(व्यवधान) बिना तुष्टिकरण किए, बिना वोट बैंक की राजनीति किए सबका साथ, सबका विकास मंत्र पर हम काम करते रहे हैं। …(व्यवधान)

21 24 hrs

At this stage, Shri Thota Narasimham and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष: नरसिम्हम जी, आप अपनी सीट पर जाइए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Thota Narasimhan, you will have to listen.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Anurag Singh Thakur, please go to your seat.

… (*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र मोदी : माननीय अध्यक्षा जी, पहले भी 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Thota Narasimhan, this is not proper. You have to go to your seat.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Ramesh Bidhuri, please go to your seat.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाइए। मैं देख रही हूं, रिक्वैस्ट कर रही हूं। आप यहां क्यों खड़े हैं?

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Ram Mohan Naidu, this is not fair. You will have to listen. Please listen quietly. रिप्लाई तो आपको सुनना पड़ेगा। Please go to your seat.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go to your seat.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप लोग तो शांति से बैठ जाइए।

… (*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र मोदी : अध्यक्ष महोदया जी, सबका साथ, सबका विकास के इस मंत्र को लेकर काम करने वाली हमारी सरकार है। …(व्यवधान) 18 हजार गांवों में जो बिजली पहुंची है, यह काम पहले की सरकारें भी कर सकती थीं। अध्यक्ष महोदया, इन 18 हजार गांवों में से 15 हजार गांव पूर्वी भारत के हैं और उन 15 हजार में से भी 5 हजार गांव पूरी तरह से नॉर्थ-ईस्ट के हैं।…(व्यवधान) आप कल्पना कर सकते हैं कि इन इलाकों में कौन रहता है? हमारे आदिवासी, हमारे गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित और जंगलों में जिंदगी गुजारने वालों का बहुत बड़ा तबका रहता है।…(व्यवधान) ये क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इनके वोट के गणित में फिट नहीं होता था। उनका इस आबादी पर विश्वास नहीं था। उसी के कारण नॉर्थ-ईस्ट को अलग-थलग कर दिया गया।…(व्यवधान) हमने सिर्फ इन गांवों में बिजली ही पहुंचायी है ऐसा नहीं है, हमने कनेक्टिविटी के हर मार्ग पर तेज गति से काम किया…(व्यवधान)

गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए नहीं खोले। जब उनकी सरकारें थीं, वे इतने साल बैठे थे, वे भी गरीबों के लिए बैंकों के दरवाजे खोल सकते थे। लगभग 32 करोड़ जन-धन खाते खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है और आज

80 हजार करोड़ रुपये इन गरीबों ने बचत करके इन जन-धन एकाउंट्स में जमा किए हैं। माताओं-बहनों के लिए, उनके सम्मान के लिए आठ करोड़ शौचालय बनाने का काम इस सरकार ने किया है। ये पहले की सरकारें भी कर सकती थीं।

उज्ज्वला योजना से साढ़े चार करोड़ गरीब माताओं-बहनों को आज धुआं मुक्त जिंदगी और बेहतर स्वास्थ्य का काम - यह विश्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये वे लोग थे, जो नौ सिलेंडर या बारह सिलेंडर इसी की चर्चा में खोए हुए थे, उनके अविश्वास के बीच वे जनता को भटका रहे थे। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार बीते दो वर्षों में पांच करोड़ देशवासी भीषण गरीबी से बाहर आए हैं। बीस करोड़ गरीबों को मात्र 90 पैसे प्रतिदिन और एक रुपया महीना के प्रीमियम पर बीमा का सुरक्षा कवच भी मिला। आने वाले दिनों में आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये की बीमारी में मदद करने का एश्योरेंस इस सरकार ने दिया है। इनको इन बातों पर भी विश्वास नहीं है।

हम किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। उस पर भी इनको विश्वास नहीं है। हम बीज से लेकर बाजार तक सम्पूर्ण व्यवस्था के अंदर सुधार कर रहे हैं, सीमलैस व्यवस्थाएं बना रहे हैं। इस पर भी उनको विश्वास नहीं है। 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करके वर्षों से अटकी हुई 99 सिंचाई योजनाओं को, कुल परियोजनाओं को पूर्ण करने का काम चल रहा है। कुछ योजनाएं पूर्णता पर पहुंच चुकी हैं, कुछ का लोकार्पण हो चुका है। लेकिन इस पर भी इनका विश्वास नहीं है। हमने 15 करोड़ किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड पहुंचाया, आधुनिक खेती की तरफ किसानों को ले गए, लेकिन इस पर भी इनका विश्वास नहीं है।

महोदया, उन्होंने यूरिया में थोड़ी नीम कोटिंग करके छोड़ दिया, परंतु शत-प्रतिशत किए बिना उसका लाभ नहीं मिल सकता है। हमने शत-प्रतिशत नीम कोटिंग का काम किया, जिसका लाभ देश के किसानों को हुआ है। यूरिया की जो कमी महसूस होती थी, वह बंद हुई है, लेकिन इस पर भी इनका विश्वास नहीं है। हमने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को

विश्वास दिलाने का काम किया, हमने न सिर्फ प्रीमियम कम किया, बल्कि इंश्योरेंस का दायरा भी बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर 2016-2017 में किसानों ने करीब 1300 करोड़ रुपये बीमा के प्रीमियम के रूप में दिए, जबकि उन्हें सहायता के रूप में 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्लेम राशि दी गई है। यानी किसानों से जितना लिया गया, उससे तीन गुना ज्यादा की क्लेम राशि उनको हमने पहुंचा दी, लेकिन इन लोगों को विश्वास नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदया, एल.ई.डी. बल्ब के बारे में जरा यह बताएं तो सही कि क्या कारण है कि उनके काल खंड में एल.ई.डी. बल्ब साढ़े तीन सौ, चार सौ और साढ़े चार सौ रुपये में बिकता था? आज वह एल.ई.डी. बल्ब 40-45 रुपये पर पहुंच गया। सौ करोड़, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, सौ करोड़ एल.ई.डी. बल्ब आज बिक चुके हैं।

इतना ही नहीं 500 से ज्यादा अर्बन बॉडीज़ में 62 लाख से ज्यादा एलईडी बल्ब्स स्ट्रीट लाइट्स में लग चुके हैं और उनके कारण नगर पालिकाओं के खर्च में भी बचत हुई है। उनके समय में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां दो थीं। आज मोबाइल फोन बनाने वाली 120 कंपनियां हैं, लेकिन उनका विश्वास काम नहीं कर रहा है। युवाओं के स्वरोज़गार के लिए पहले पढ़े-लिखे नौजवानों को सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता था और वह रोजी-रोटी के लिए भटकता था। हमने मुद्रा योजना के तहत 13 करोड़ नौजवानों को लोन देने का काम किया है। इतना ही नहीं, वक्त बदल चुका है, आज दस हज़ार से ज्यादा स्टार्ट-अप हमारे देश के नौजवान चला रहे हैं और देश को इनोवेटिव इण्डिया की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। एक समय था, जब हम डिजिटल लेन-देन की बात करने लगे तो उसी समय बड़े-बड़े विद्वान लोग कहने लगे कि हमारा देश तो अनपढ़ है, डिजिटल ट्रांस्ज़ैक्शन कैसे कर सकता है? हमारे देश के गरीबों तक यह कैसे पहुंच सकता है? अध्यक्ष महोदया, जो लोग इस प्रकार से देश की जनता की ताकत को कम आंकते थे, उनको जनता ने करारा जवाब दिया है। अकेले भीम एप और मोबाइल फोन से, एक महीने में 41 हज़ार करोड़ रुपये का ट्रांस्जैक्शन हमारे देश के नागरिक आज कर रहे हैं। लेकिन उनका देश की जनता

पर विश्वास नहीं है। उनका कहना था कि ये अनपढ़ हैं, यह नहीं करेंगे, वह नहीं करेंगे। यह इनकी इसी मानसिकता का परिणाम है।

2143 hrs

At this stage, Shri Thota Narasimham and some other hon. Members went back to their seats.

अध्यक्ष महोदया, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस में 42 अंक का सुधार हुआ है। इनको अब उस पर भी शक होने लगा है। ये उन संस्थाओं पर भी अविश्वास करने लगे हैं। ग्लोबल कम्पीटेटिव इन्डैक्स में 31 अंकों का सुधार हुआ है। उसमें भी इनको शक हो रहा है। इनोवेशन इन्डैक्स में 24 अंकों का सुधार हुआ है। हमारी सरकार ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस को सुधार कर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नस को कम कर रही है। मेक इन इण्डिया हो या जीएसटी हो, इन पर भी इनका विश्वास नहीं है। भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की इकॉनमिक ग्रोथ को मज़बूती दी है । बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था में भारत छठे नंबर की अर्थव्यवस्था है। यह जयकारा सरकार में बैठे हुए लोगों का नहीं है, बल्कि सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानियों के पुरुषार्थ का है। इसके लिए तो गौरव करना सीखो। लेकिन वे भी गौरव करना नहीं जानते हैं । पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने की दिशा में आज देश तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। हमने काले धन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है और यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है । मैं जानता हूँ कि इसके कारण कैसे-कैसे लोगों को परेशानी हो रही है। उनके वे घाव अभी भी भर नहीं रहे हैं । यह तो आपके व्यवहार से हमें पता चलता है । हमने टैक्नोलॉजी का उपयोग किया और टैक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी खजाने से निकले हुए रुपये जो कहीं और चले जाते थे, उसमें 90 हज़ार करोड़ रुपये बचाने का काम टैक्नोलॉजी के माध्यम से हमने किया है । वह पैसा गलत हाथों में जाता था, किस प्रकार की व्यवस्थाओं से चलता था, यह देश भली भाँति जानता है। ढाई लाख से ज्यादा शैल कंपनियों को हमने ताले लगा दिए, और भी करीब दो-सवा दो लाख कंपनियां आज भी नज़र में हैं एवं कभी भी उन पर ताला लगने की संभावना है। क्योंकि इनको पनपाया किसने? कौन सी ताकतें थीं, जो

उनको बढ़ावा देती थी और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने खेल खेले जा रहे थे? यह सबको पता है।

बेनामी सम्पत्ति का कानून सदन ने पारित किया, लेकिन 20 साल तक उसे नोटिफाई नहीं किया गया। क्यों, किसको बचाना चाहते थे? हमने आकर इस काम को भी किया और मुझे खुशी है कि अब तक चार-साढ़े चार हजार करोड़ रुपये की सम्पत्ति इस बेनामी सम्पत्ति कानून के तहत जब्त कर दी गई है। देश को विश्वास है, दुनिया को विश्वास है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं को विश्वास है, लेकिन जो खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, वे हम पर विश्वास कैसे कर सकेंगे। यह सब ऐसे नहीं होता है। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है।

"धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम्"

यानी चातक पक्षी के मुँह में बारिश की बूँद सीधे नहीं गिरती तो इसमें बादल का क्या दोष।

महोदया, कांग्रेस को खुद पर अविश्वास है। ये अविश्वास से घिरे हुए हैं। अविश्वास ही उनकी पूरी कार्यशैली, उनके सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। उनको विश्वास नहीं है। स्वच्छ भारत पर भी विश्वास नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी विश्वास नहीं, देश के मुख्य न्यायाधीश पर भी विश्वास नहीं, रिजर्व बैंक पर भी विश्वास नहीं, अर्थव्यवस्था के आंकड़े देने वाली संस्थाओं पर भी उनको विश्वास नहीं है। देश के बाहर पासपोर्ट की ताकत क्या बढ़ रही है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरवगान कैसे हो रहा है, उस पर भी उनको विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, ईवीएम पर विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको अपने पर विश्वास नहीं है। यह अविश्वास क्यों बढ़ गया? जब कुछ मुट्ठी भर लोग अपना ही विशेषाधिकार मानते थे, अपना ही विशेष अधिकार मानकर जो बैठे थे, जब यह जनाधिकार में परिवर्तित होने लगा तो जरा वहाँ पर बुखार चढ़ने लगा, परेशानी बढ़ने लगी। जब प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की परम्पराओं को बंद किया गया तो उनको परेशानी होना स्वाभाविक था। जब भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार होने लगा तो उनको परेशानी होनी बहुत स्वाभाविक था। जब भ्रष्टाचार की कमाई आनी बंद हो गई तो उनकी बैचेनी बढ़ गई, यह भी

साफ है। जब कोर्ट, कचहरी में उन्हें भी पेश होना पड़ा तो उनको भी जरा तकलीफ होने लगी है। मैं हैरान हूँ, यहाँ ऐसे विषयों को स्पर्श किया गया, आजकल शिव भक्ति की बातें हो रही हैं। मैं भी भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ, मैं सवा सौ करोड़ देशवासियों से भी प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको इतनी शक्ति दें कि वर्ष 2024 में आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव ले आयें। मेरी आपको शुभकामनायें हैं।

यहाँ पर डोकलाम की चर्चा की गई। मैं मानता हूँ कि जिस विषय की जानकारी नहीं है, कभी-कभी उस पर बोलने से बात बड़ी उलटी पड़ जाती है। उसमें व्यक्ति का नुकसान कम है, देश का नुकसान हो जाता है। इसलिए ऐसे विषयों पर बोलने से पहले थोड़ा संभालना चाहिए। हमें एक घटनाक्रम याद रहना चाहिए। जब सारा देश, सारा तंत्र, सारी सरकार एकजुट होकर के डोकलाम के विषय को लेकर प्रवृत्तिशील थी, अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल रही थी।

जो आज डोकलाम की बातें करते हैं, तब वे चीन के राजदूत के साथ बैठते हैं। बाद में 'कभी ना तो कभी हाँ' जैसे यह फिल्मी अंदाज में चल रहा था, नाटकीय ढंग से चल रहा था। कोई कहता था कि वे मिले हैं, कोई कहता था कि नहीं मिले हैं। क्यों भाई, ऐसा सस्पेंस क्यों? कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो साफ मना कर दिया था कि उनके उपाध्यक्ष चीनी राजदूत से मिले ही नहीं हैं। इस बीच एक प्रेस विज्ञप्ति भी आ गई और फिर कांग्रेस को यह मानने को मजबूर होना पड़ा कि हां, मुलाकात तो हुई थी। क्या देश के विषयों में कोई गम्भीरता नहीं होती है? क्या हर जगह पर बचकाना हरकतें करते रहेंगे?

यहां पर राफेल विवाद को छेड़ा गया । मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सत्य को इस प्रकार से कुचला जा सकता है, सत्य को इस प्रकार से रौंदा जा सकता है। अब बार-बार चीख-चीख कर देश को गुमराह करने का काम किया जाता है। इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ही क्या इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं? यह देश उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह कितना दु:खद है कि इस सदन में लगाए गए आरोपों पर दोनों देशों को बयान जारी करना पड़ा और दोनों देशों को खंडन करना पड़ा। क्या हम ऐसी बचकाना हरकतें करते रहेंगे? क्या कोई जिम्मेदारी है या

नहीं? जो लोग इतने सालों तक सत्ता में रहे हैं, बिना हाथ-पैर के, बिना कोई सबूत के बस चीखते रहो, चिल्लाते रहो। यह सत्य का गला घोंटने की कोशिश है। देश की जनता इसे भली-भाँति जानती है। हर बार जनता ने आपको जवाब दिया है। अब सुधरने का मौका है, सुधरने की कोशिश कीजिए। राजनीति का यह स्तर देशहित में नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, देशवासियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह समझौता दो देशों के बीच हुआ है। यह कोई व्यापारिक पार्टियों के साथ नहीं हुआ है। यह दो जिम्मेदार सरकारों के बीच हुआ है और पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। मेरी प्रार्थना भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, इतने संवेदनशील मुद्दे पर इन बचकाना बयानों से बचा जाए। यह मेरा आग्रह भी है। नामदार के आग्रह में मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं क्योंकि हमने देखा है कि एक ऐसी प्रवृत्ति बन चुकी है कि देश के सेनाध्यक्ष के लिए कैसी भाषा का प्रयोग किया गया। क्या ऐसा कभी होता है? क्या देश के सेनाध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? आज भी हिन्दुस्तान का हर सिपाही, जो सीमा पर होगा या निवृत्त होगा, उसे आज इतनी गहरी चोट पहुंची होगी, जिसकी कल्पना हम सदन में बैठकर नहीं कर सकते। जो देश के लिए मर-मिटने के लिए निकले हैं, जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, उस सेना के जवानों के पराक्रमों को स्वीकारने का आपको सामर्थ्य नहीं होगा। लेकिन, क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोलें? आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोलें, यह देश कभी माफ नहीं कर सकेगा। आपको गालियां देनी हो तो मोदी मौजूद है। आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार है, लेकिन देश के जवान, जो मर-मिटने के लिए निकले हैं, उनको गालियां देना बंद कीजिए।

सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोलते हैं, इस प्रकार से सेना को अपमानित करने का काम निरंतर चलता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा यह अविश्वास कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस ने देश में अस्थिरता फैलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की संवैधानिक व्यवस्था का

दुरुपयोग किया। हमने अखबार में पढ़ा कि अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकृति के तुरंत बाद बयान दिया गया, कौन कहता है हमारे पास नंबर नहीं है, यह अहंकार देखिए। मैं इस सदन को वर्ष 1999 को याद कराना चाहता हूँ, राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े होकर दावा किया गया था कि हमारे पास तो 272 की संख्या है और हमारे साथ और भी जुड़ने वाले है और अटल जी की सरकार को सिर्फ एक वोट से गिरा दिया गया, लेकिन खुद जो 272 का दावा किया था, वह खोखला निकला और 13 महीनों में देश को चुनाव के अंदर जाना पड़ा। देश पर चुनाव थोपे गए।

माननीय अध्यक्ष महोदया, आज फिर एक स्थिर जनादेश को अस्थिर करने के लिए खेल खेला जा रहा है। राजनीति अस्थिरता के द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि करना, यह कांग्रेस की फितरत रही है। वर्ष 1979 में किसान नेता, माटी के लाल चौधरी चरण सिंह जी को पहले समर्थन का भ्रम दिया गया और फिर वापिस ले लिया। एक किसान, एक कामगार का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? चंद्रशेखर जी का भी उसी तरह मॉडस ऑपरेन्डी वही था। पहले सहयोग की रस्सी फेंको और फिर धोखे से उसे वापिस खीचों। यही खेल चलता रहा। यही फार्मूला वर्ष 1997 में फिर अपनाया गया, पहले आदरणीय देवगौड़ा जी को अपमानित किया गया और फिर इंद्र कुमार गुजराल जी की बारी आई।…(व्यवधान) क्या देवगौड़ा जी हों, क्या मुलायम सिंह यादव जी हों, कौन भूल सकता है कि कांग्रेस ने लोगों के साथ क्या किया। जमीन से उठे, अपने श्रम से लोगों के हृदय में जगह बनाने वाले जन नेता के रूप में उभरे हुए उन नेताओं तथा दलों को कांग्रेस ने छला है और बार-बार देश को अस्थिरता में धकेलने का पाप किया है। कैसे कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाने के लिए दो-दो बार विश्वास को खरीदने का प्रयास किया। वोट के बदले नोट, यह खेल कौन नहीं जानता।…(व्यवधान)

आज यहाँ एक बात और कही गई, यहाँ पूछा गया कि प्रधानमंत्री अपनी आँख में मेरी आँख भी नहीं डाल सकते।…(व्यवधान)

22 00 hrs

माननीय अध्यक्ष महोदया, यह सही है। हम कौन होते हैं, जो आपकी आंख में आंख डाल सकें? गरीब मां का बेटा, पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया हुआ, आप तो नामदार हैं नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं है। हम नहीं डाल सकते हैं। इतिहास गवाह है, सुभाष चंद्र बोस ने कभी आंख में आंख डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। मोरारजी भाई देसाई गवाह हैं, उन्होंने आंख में आंख डालने की कोशिश की, क्या किया गया। जयप्रकाश नारायण गवाह हैं, उन्होंने आंख में आंख डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। चौधरी चरण सिंह, उन्होंने आंख में आंख डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने आंख में आंख डालने की कोशिश की उनके साथ क्या किया गया। …(व्यवधान) चंद्रशेखर जी ने आंख में आंख डालने की कोशिश की, क्या किया गया।…(व्यवधान) प्रणब मुखर्जी ने आंख में आंख डालने की कोशिश की, क्या किया गया। …(व्यवधान) इतना ही नहीं हमारे शरद पवार जी ने आंख में आंख डालने की कोशिश की थी, उनके साथ भी क्या किया गया था।…(व्यवधान) मैं सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूं। आंख में आंख डालने की कोशिश करने वालों को कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे उनको ठोकर मारकर निकाला जाता है, एक परिवार का इतिहास, इस देश में कोई अंजान नहीं है। हम तो कामदार हैं, भला हम नामदार की आंख में आंख कैसे डाल सकते हैं? आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने, आज इसे टीवी पर पूरा देश देख रहा है कि कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, यह आंखों का खेल। माननीय अध्यक्ष महोदया, आंख में आंख डाल करके सत्य को कुचला गया है। सत्य को बार-बार कुचला गया है, बार-बार रौंदा गया है। यहां कहा गया कि कांग्रेस ही थी, जीएसटी में पेट्रोलियम को क्यों नहीं लाए? मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अपने परिवार के इतिहास के बाहर भी तो कांग्रेस का इतिहास है। अपने परिवार के बाहर कांग्रेस सरकारों का भी इतिहास है। अरे जरा इतना तो ध्यान रखो, जब यूपीए सरकार थी, तब पेट्रोलियमों को जीएसटी के बाहर रखने का निर्णय आपकी सरकार ने किया था।…(व्यवधान) आपको यह भी

मालूम नहीं है। आज यहां यह भी कहा गया ...(व्यवधान) मैं आपका विषय लेने वाला हूं। जयदेव जी, मैं आपकी बात लेने वाला हूं। ...(व्यवधान) आपका विषय आएगा। ...(व्यवधान) जरा बारी-बारी से आने दो। ...(व्यवधान) किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं, आप चिंता मत कीजिए। ...(व्यवधान) हर किसी का सम्मान करूंगा। आप चिंता मत कीजिए। ...(व्यवधान)

आज यहां यह भी बात कही गई कि आप चौकीदार नहीं, भागीदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं हैं, ठेकेदार नहीं है। न हम सौदागर हैं, न ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं। हम देश के नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं।

देश में 115 आकांक्षी जिले हैं, हम उनके विकास में सपनों के भागीदार हैं। हम देश को विकास की नई राह पर ले जाने वाले मेहनतकश मजदूरों के भागीदार हैं। हम भागीदार हैं और भागीदार रहेंगे। उनके दुखों को बांटना, यह हमारी भागीदारी और जिम्मेवारी है, इसे हम निभाएंगे। हम ठेकेदार नहीं हैं, हम सौदागर नहीं हैं। हम चौकीदार भी हैं, भागीदार भी हैं। हमें इस बात पर गर्व है। कांगेस का एक ही मंत्र है - या तो हम रहेंगे, अगर हम नहीं हुए तो फिर देश में अस्थिरता रहेगी, अफवाहों का साम्राज्य रहेगा, आप पूरा कालखंड देख लीजिए। वहां भी भुक्तभोगी बैठे हुए हैं, सबके साथ क्या हुआ, सभी को मालूम है। अफवाहें उड़ाई जाती हैं, ...* फैलाया जाता है। अब अफवाह फैलाने के लिए देश में टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है। आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों पर अत्याचार रोकने वाला कानून खत्म कर दिया गया है। देश को हिंसा की आग में झोंकने का षडयंत्र किया जाता है।

अध्यक्ष महोदया जी, ये लोग दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों और गरीबों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके राजनीति करते रहे हैं। कामगारों और किसानों की दुखों की चिंता किए बिना,

---

* Not recorded

उनकी समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने की बजाय चुनाव जीतने के शार्टकट रास्ता ढूंढने का प्रयास इस देश में हुआ है। उसी का कारण है कि देश का एक बहुत बड़ा तबका सशक्तीकरण से वंचित रह गया। बाबा साहब अम्बेडकर की भाषा और उनके पहनावे, उनकी राजनीति का मजाक उड़ाने वाले लोग आज बाबा साहब के गीत गाने लगे हैं।

महोदया, धारा 356 का बार-बार दुरुपयोग करने वाले लोग हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की बातें करते हैं। जो मुख्य मंत्री पसंद नहीं आता था, उसको हटाना, अस्थिरता पैदा करना, यह खेल देश आजाद होने के तुरंत बाद शुरू कर दिया गया, कभी भी मौका नहीं छोड़ा गया। इसी नीति का परिणाम वर्ष 1980, 1991, 1998 और 1999 देश को समय से पहले चुनाव के अंदर घसीटा गया, चुनाव में जाना पड़ा। एक परिवार के सपने और आकांक्षा के सामने जो भी आया, उसके साथ यही बर्ताव किया गया। चाहे देश के लोकतंत्र को ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े। यह स्वाभाविक है, जिनकी ऐसी मानसिकता है, जिनके अंदर इतना अहंकार है, वह हम लोगों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हमारा यहां बैठना कैसे गवारा हो सकता है, यह हम भलीभांति समझते हैं, इसलिए हमें नापसंद करना बहुत स्वाभाविक है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, कांग्रेस पार्टी जमीन से कट चुकी है। वे तो डूबे हैं उनके साथ जाने वाले भी डूबेंगे। हम भी डूबे हैं सनम तुम भी डूबो। इनका भी यही हाल होने वाला है। मैं अर्थ और अनर्थ में हमेशा उलझे हुए और अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानने वाले और जिन्हें विद्वता का अहंकार है, अर्थ और अनर्थ में हमेशा उलझे हुए एक व्यक्ति ने बात बताई थी, मैं उन्हीं के शब्दों को क्वोट करना चाहता हूं।

> "कांग्रेस पार्टी अलग-अलग राज्यों में क्यों और कैसे कमजोर हो गई? मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं, जहां इस पार्टी का प्रभुत्व समाप्त हो गया है। क्यों कांग्रेस इस बात का समझ नहीं पाई कि सत्ता अब उच्च वर्ग, साधन सम्पन्न वर्गों से गांव-देहात के लोगों, इंटरमीडिएट कास्ट्स और यहां तक कि ऐसी जातियों, जो कथित सोशल ऑर्डर में सबसे नीचे हैं, गरीब, बेरोजगार, जिनके पास सम्पत्ति नहीं है, जिनकी

कोई आमदनी नहीं है, जिनकी आवाज आज तक सुनी नहीं गई, उन तक पहुंची है। जैसे-जैसे पावर नीचे की तरफ चलती गई, जैसा कि लोकतंत्र में होना चाहिए, वैसे-वैसे अनेक राज्यों में कांग्रेस का प्रभाव खत्म होता गया।"

यह एक कोटेबल कोट है। यह 11 अप्रैल, 1997 का है। जब देवगौड़ा जी की सरकार का विश्वास प्रस्ताव चल रहा था, उस समय अर्थ और अनर्थ में उलझे हुए, आपके विद्वान महारथी, श्रीमान चिदम्बरम जी का यह वाक्य है। कुछ विद्वान लोगों की बातें वहां शायद समझ में नहीं आई होंगी।

18 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने तीन राज्यों का गठन किया था – उत्तराखण्ड, झारखण्ड और छत्तीसगढ़। कोई खींचतान नहीं, न कोई झगड़ा हुआ, मिल-बैठकर, जो जहां से निकले, उनके साथ बैठकर रास्ते निकाले और तीनों राज्य बहुत तेजी से शान्ति से प्रगति कर रहे हैं और देश के विकास में हिस्सेदारी कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक लाभ पाने के लिए, आन्ध्र प्रदेश के लोगों को विश्वास में लिए बिना, राज्य सभा के दरवाजों को बन्द करके, जोर और जुल्म के बीच, हाउस ऑर्डर में नहीं था, तब भी आपने आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन किया।...(व्यवधान) यह बात सही है। जैदेव जी ने बताया और यह बात सही है कि उस समय मैंने कहा था – 'तेलुगू हमारी मां है। तेलुगू की स्पिरिट को टूटने नहीं देना चाहिए। उन्होंने बच्चे को बचा लिया और मां को मार दिया है। हम सबका दायित्व है कि तेलुगू स्पिरिट को बचा लिया जाए।' ये शब्द मेरे उस समय थे और आज भी मैं ऐसा मानता हूं। ...(व्यवधान) वर्ष 2014 में आपका क्या हाल हुआ? आपको लगता था कि एक जाएगा तो जाएगा, लेकिन दूसरा मिल जाएगा। लेकिन जनता इतनी समझदार थी कि न यह मिला, न वह मिला और आप अपने पीछे यह मुसीबत छोड़कर चले गए। यह आपके लिए नया नहीं है। आपने भारत-पाकिस्तान का विभाजन किया, हम आज भी मुसीबतें झेल रहे हैं। आपने इनका विभाजन भी ऐसे ही किया है। आपने उनको विश्वास दिलाया होता तो शायद यह मुसीबत न आती, लेकिन कुछ नहीं सोचा। ...(व्यवधान) मुझे बराबर

याद है, चन्द्रबाबू नायडू का और तेलंगाना के सीएम केसीआर का पहले साल बंटवारे को लेकर तनाव रहता था, झगड़े होते थे। गवर्नर को बैठना पड़ता था, होम मिनिस्टर को बैठना पड़ता था, कभी मुझे बैठना पड़ता था। उस समय टीडीपी की पूरी ताकत तेलंगाना के खिलाफ लगी थी। उसी में लड़ते रहते थे। हम उनको शान्त करने की बहुत कोशिश करते थे, संभालने की कोशिश करते थे। टीआरएस ने मेच्योरिटी दिखाई, वे अपने आप विकास में लग गए। उधर क्या हाल हुआ, आप जानते हैं। संसाधनों का विवाद आज भी चल रहा है। आप लोगों ने ऐसा बंटवारा किया कि संसाधनों का विवाद आज भी चल रहा है।

एनडीए की सरकार ने सुनिश्चित किया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विकास में कोई कमी नहीं आएगी और हम पूरी तरह उसमें कमीटेड हैं। हम ने जो कदम उठाए, मुझे कुछ मीडिया रिपोर्टें याद हैं, मुझे मीडिया रिपोर्ट याद आ रही है। इसी सदन के टीडीपी के एक माननीय सदस्य ने ब्यान दिया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से कहीं ज्यादा, बेहतर स्पेशल कैटेगरी है। यह लोगों ने दिया था। मैं वित्त आयोग की सिफारिश को फिर से दोहराना चाहता हूं। इस सिफारिश के तहत आयोग ने स्पेशल और जनरल कैटेगरी राज्यों के भेद को समाप्त कर दिया। …(व्यवधान) आयोग ने एक नई कैटेगरी नॉर्थ-ईस्टर्न को और हिल स्टेट की बना दी। इस प्रक्रिया में आयोग ने इस बात का ध्यान रखा है कि अन्य राज्यों को आर्थिक नुकसान न हो। एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश के लोगों की आशा-आकांक्षाओं का सम्मान करती है। …(व्यवधान) आप पूरी बात सुनिए, आपकी काम की बात आ रही है।…(व्यवधान) एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश के लोगों की आशा और आकांक्षाओं का सम्मान करती है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकार 14वें वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों से बंधी हुई है। इसलिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नया स्पेशल असिस्टेंस पैकेज बनाया गया, जिससे राज्य को उतनी वित्तीय सहायता मिले, जितनी उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने से प्राप्त होती है। इस निर्णय को 8 सितम्बर, 2016 को लागू किया गया। 4 नवम्बर, 2016 को आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने स्वयं इस पैकेज को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। एनडीए सरकार आंध्र रिऑर्गनाइजैशन एक्ट और स्पेशल असिस्टैंस पैकेज पर

किए हुए हर कमिटमेंट को पूरा करना चाहती थी, लेकिन टीडीपी ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए यू-टर्न किया और माननीय अध्यक्ष महोदया जी, जब टीडीपी ने एनडीए छोड़ने के लिए तय किया तो मैंने चंद्रबाबू को फोन किया था। यह जानकारी आपके लिए नई होगी। …(व्यवधान)

22 18 hrs

At this stage Dr. Ravindra Babu and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

यह आपके काम की जानकारी है।…(व्यवधान) टीडीपी एनडीए से निकले, चंद्रबाबू से फोन पर मेरी बात हुई और मैंने चन्द्रबाबू से कहा था कि बाबू, आप वाईएसआर कांग्रेस के जाल में फंस रहे हो । आप वाईएसआर कांग्रेस के चक्र में फंस रहे हो । मैंने कहा कि आप वहां की स्पर्धा में…(व्यवधान) आप किसी हालत में बच नहीं पाएंगे। …(व्यवधान) यह मैंने एक दिन उनको कहा था। …(व्यवधान) मैं वह देख रहा हूं। झगड़ा उनका वहां का है और उपयोग सदन का किया जा रहा है।…(व्यवधान) आंध्र प्रदेश की जनता भी इस घनघोर अवसरवादिता को देख रही है। …(व्यवधान) चुनाव नजदीक आते गए और प्रशंसा आलोचना में बदल गई।…(व्यवधान) कोई भी विशेष इंसेंटिव या पैकेज देते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता है। …(व्यवधान) इसी सदन में तीन साल पहले श्रीमान वीरप्पा मोइली जी ने कहा था।

> "How you can create this kind of an inequality between one State and the other State? It is a major issue. After all, you are an arbitrator."

यह बात मोइली जी ने कही थी और मैं आज इस सदन के माध्यम से आंध्र के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे राजधानी का काम हो, चाहे किसानों की भलाई का काम हो, केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार आंध्र की जनता के कल्याण के काम में कभी पीछे नहीं रहेगी और उनकी जो मदद कर सकते हैं, करते रहेंगे। आंध्र का भला हो और उसी में देश का भला हो, यह हमारी सोच है। हम विकास के काम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा प्रयास, हमारा काम करने का

तरीका समस्याओं को सुलझाने का है। 'वन रैंक वन पेंशन' को दशकों तक लटकाने वाले कौन थे? जीएसटी का विषय इतने वर्षों तक किसने लटका कर रखा था? आज यहां बताया गया कि गुजरात के मुख्य मंत्री ने इसे रोका था। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं और उस समय के जो कर्ताधर्ता थे, उन्हें भी मालूम है। मेरी मुख्य मंत्री के नाते भेजी गई चिट्ठियां भी मौजूद हैं। मैंने भारत सरकार को कहा था कि जीएसटी में राज्यों के कंसर्न को एड्रेस किए बिना आप जीएसटी को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। राज्यों ने जो-जो मुद्दे उठाए हैं, आप राज्यों के साथ बैठकर उन मुद्दों का समाधान कीजिए, लेकिन उनका अहंकार इतना था कि वे राज्यों की एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैं आज यह रहस्य भी खोलता हूं कि बीजेपी के सिवाय अन्य दलों के मुख्य मंत्री भी, जिनमें कांग्रेस के मुख्य मंत्री भी थे, वे मुझे मीटिंग्स में मिलते थे और कहते थे कि हम तो बोल नहीं पाएंगे, मोदी जी आप बोलिए। इससे हमारे राज्य का भी कुछ भला हो जाएगा। मैंने आवाज उठाई थी। जब मैं प्रधान मंत्री बना, तब मेरा मुख्य मंत्री का अनुभव काम आया। उस अनुभव के कारण सभी राज्यों के कंसर्न को एड्रेस करने का काम किया। सभी राज्यों को ऑन बोर्ड लाने में हम सफल हुए। अगर आपका अहंकार न होता, आपने राज्यों की समस्याओं को समझा होता, तो जीएसटी पांच साल पहले आ जाता, लेकिन आपके काम का तरीका लटकाने का रहा है।

काले धन पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के लिए कहा था । उस विषय को कौन लटका कर बैठा था? उसे आप लोगों ने लटकाया था। बेनामी सम्पत्ति कानून किसने लटका कर रखा था?

अध्यक्षा जी, एनडीए सरकार द्वारा खरीफ के समय में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की लागत 150 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसे किसने रोका था? आपके पास यह रिपोर्ट वर्ष 2006 से पड़ी थी और आप वर्ष 2014 तक सरकार में थे। आठ साल तक आपको रिपोर्ट याद नहीं आई। हमने निर्णय किया था कि हम किसानों को एमएसपी डेढ़ गुना करके देंगे और हमने करके दिखाया। जब यूपीए सरकार ने वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कृषि नीति का ऐलान किया, उसमें पचास प्रतिशत वाली बात तो खा गई, उसे गायब कर दिया गया । उसके आगे

भी सात साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन एमएसपी के लिए सिर्फ बातें करते रहे और जनता को, किसानों को गलत विश्वास देते रहे।

अध्यक्षा जी, मैं आज एक बात और बताना चाहता हूं। देश के लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्हें इसे सुनना नहीं है, यह उनके काम आने वाली नहीं है, लेकिन देश के लिए जरूरी है। हम वर्ष 2014 में सत्ता में आए। तब कई लोगों ने हमें कहा था कि इकोनॉमी पर व्हाइट पेपर लाया जाए। यह बात हमारे मन में भी थी कि व्हाइट पेपर लाएंगे, लेकिन जब शुरू में हम सारी जानकारी प्राप्त करने लगे, तब एक के बाद एक ऐसी जानकारी आई कि हम चौंक गए कि अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है।

इसलिए मैं आज एनपीए की कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या परिस्थितियाँ पैदा की गईं? वर्ष 2008 में इस कहानी की शुरुआत हुई और वर्ष 2009 में चुनाव था। कांग्रेस को लगने लगा था कि अब एक साल बचा है, जितने बैंकों को खाली कर सकते हो, करो। जब एक बार इसकी आदत लग गयी, तो बैंकों की अंडरग्राउंड लूट वर्ष 2009 के बाद वर्ष 2014 तक चलती रही। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब तक बैंकों को लूटने का खेल चलता रहा।

एक आँकड़ा इस सदन के लोगों को भी चौंका देगा। आजादी के साठ वर्षों के बाद हमारे देश के बैंकों ने लोन के रूप में जो धनराशि दी थी, वह 18 लाख करोड़ रुपये थी। 60 वर्षों में 18 लाख करोड़ रुपये थी। लेकिन, वर्ष 2008 से वर्ष 2014 के बीच, मात्र छह साल में यह राशि 18 लाख करोड़ रुपये से 52 लाख करोड़ रुपये हो गई। साठ साल में 18 लाख करोड़ रुपये ओर छह साल में 52 लाख करोड़ तक पहुँचाई गई। 60 वर्षों में जो हुआ था, उसको इन छह वर्षों में डबल कर दिया गया। यह कैसे हुआ?

दुनिया में इंटरनेट बैंकिंग तो बहुत देर से आई। लेकिन, कांग्रेस के ऐसे बुद्धिमान लोग हैं कि दुनिया में इंटरनेट बैंकिंग आने से पहले भारत में फोन बैंकिंग शुरू हुई। टेलीफोन बैंकिंग शुरू हुई। टेलीफोन बैंकिंग का यह कमाल था कि छह साल में 18 लाख करोड़ रुपये से 52 लाख करोड़ रुपये अपने चहेते लोगों के लिए बैंकों से खज़ाना लुटा दिया गया। उसका क्या तरीका था? कागज

वगैरह कुछ नहीं देखना था, केवल टेलीफोन आता था कि लोन दे दो। लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन दे दो, उसके बाद कोई और लोन दे दो। जो गया सो गया, पैसे जमा कराने के लिए नए लोन देते जाओ। यही कुचक्र चलता गया और देश तथा देश के बैंक एनपीए के विशाल जंजाल में फंस गए। एनपीए का जंजाल एक प्रकार से भारत की बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक लैंड माइन की तरह बिछाया गया था। हमने पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी जाँच शुरू की। एनपीए की सही स्थिति क्या है, इसके लिए मैकेनिज्म शुरू किया गया। इस मामले में, हमने इतनी बारीकी से जाँच की कि एनपीए का जाल गहराता गया, निरंतर गहराता गया।

एनपीए बढ़ने का एक और कारण यह है कि यूपीए सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिये, जिसके कारण कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट में बेतहाशा वृद्धि हुई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कैपिटल गुड्स का इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी को कम करके इतना ज्यादा बढ़ाया गया कि हमारे कच्चे तेल के आयात के समतुल्य हो गया। इन सारे इम्पोर्ट्स की फाइनेंसिंग बैंकों द्वारा लोन लेकर की गयी। देश में कैपिटल गुड्स के उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बैंकों की लेंडिंग के बिना, प्रोजेक्ट एसेसमेंट के बिना, क्लीयरेंस दे दी गयी। यहाँ तक कि बहुत-से प्रोजेक्ट्स में तो इक्विटी के बदले भी बैंकों ने लोन दिया।

अब एक तरफ तो इन कैपिटल गुड्स के आयात और प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए कस्टम ड्यूटी और सरकार के टैक्स में कमी की गई। वहीं दूसरी तरफ सरकारी क्लियरेंस देने के लिए कुछ नए टैक्स बनाए गए, जिन टैक्स का पैसा सरकार के खाते में नहीं जाता था। इस टैक्स के कारण सारे प्रोजेक्ट्स के क्लियरेंस में देरी हुई। बैंकों के लोन फंसे रहे और एन.पी.ए. बढ़ता रहा। आज विपक्ष के मित्र जब बार-बार एन.पी.ए. की स्थिति पर बयान देते हैं, तो सरकार को बाध्य होकर देश की जनता के सामने इस सदन के माध्यम से कुछ तथ्य फिर से रखने की जरूरत पड़ी है।

एक तरफ हमारी सरकार ने बैंकों की बुक्स में इन सभी एन.पी.एज़. को ईमानदारी के साथ दिखाने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरी तरफ हमने बैंकों में सुधार के लिए बहुत सारे नीतिगत निर्णय लिए, जो देश की अर्थव्यवस्था को आने वाले वर्षों में मदद पहुंचाएंगे। 50 करोड़ रुपये से

ज्यादा के सभी एन.पी.ए. अकाउंट्स की समीक्षा की गई है। इनमें विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉड्स की संभावना का आकलन किया जा रहा है। बैंकों में स्ट्रेस्ड एसेट्स के मैनेजमेंट के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की गई है। दो लाख दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बैंकों के रीकैपिटलाइज़ेशन के लिए दी जा रही है।

हमारी सरकार ने इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बनाए हैं। इसके द्वारा टॉप 12 डिफॉल्टर्स, जो कि कुल एन.पी.ए. के 25 प्रतिशत के बराबर हैं, के केस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा लिए जा चुके हैं। इन 12 बड़े केसों में लगभग तीन लाख करोड़ रुपये की राशि फंसी हुई है। सिर्फ एक साल में इनमें से तीन बड़े मामलों में हमारी सरकार ने लगभग 55 प्रतिशत की रिकवरी पाई है। वहीं अगर इन 12 बड़े मामलों की बात करें, तो उनमें से लगभग 45 प्रतिशत की रिकवरी की जा चुकी है। ऐसे लोगों के लिए ही कल लोक सभा ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल पास किया है। बैंकों का कर्ज न चुकाने वालों के लिए अब देश के कानून से बचना और मुश्किल हो गया है। इससे एन.पी.ए. पर नियंत्रण करने में भी मदद मिलेगी। अगर वर्ष 2014 में एन.डी.ए. सरकार न बनती और जिस तरीके से कांग्रेस सरकार देश चला रही थी, अगर वही व्यवस्था चलती रहती तो देश आज बहुत बड़े संकट में होता।

मैं इस सदन के माध्यम से देश को यह बताना चाहता हूं कि पहले की सरकार देश में स्पेशल फॉरेन करेन्सी नॉन रेसिडेंट डिपॉज़िट यानी एफ.सी.एन.आर. का लगभग 32 मिलियन डॉलर का कर्ज छोड़कर गई थी। इस कर्ज को भी आज भारत पूरी तरह वापस कर चुका है। यह काम हमने कर दिया है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में ग्राम स्वराज अभियान को आगे बढ़ाने के लिए और महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए हमने 15 अगस्त तक 65 हजार गांवों में सभी लोगों के पास बैंक खाता हो, गैस कनेक्शन हो, हर घर में बिजली हो, सभी का टीकाकरण हुआ हो, सभी को बीमा सुरक्षा कवच मिला हो और हर घर में एल.ई.डी. बल्ब हो, के लिए कार्य किया है। ये

गांव उन 115 जिलों में हैं, जिनको गलत नीतियों ने पिछड़ेपन का अविश्वास दिया और हमने उनको आकांक्षा का नया विश्वास दिया।

न्यू इंडिया की व्यवस्थाएं स्मार्ट भी हैं, सेंसेटिव भी हैं। स्कूलों में लैब्स के ठिकाने नहीं थे, हमने अटल टिंकरिंग लैब, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया अभियानों से प्रतिभागी और पहचान बढ़ा दिया।...(व्यवधान) महिलाओं के लिए जीवन के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गईं। मैं आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि केबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में पहली बार दो महिला मंत्री बैठती हैं और वे निर्णय में भागीदार होती हैं। महिलाएं फाइटर पायलट के तौर पर इंडक्ट की गई हैं।...(व्यवधान) तीन तलाक झेल रही मुस्लिम बहनों के साथ सरकार मजबूती के साथ खड़ी है।...(व्यवधान) बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जन-आंदोलन बन चुका है। अनेक जिलों में बेटियों के जन्म में बढ़ोतरी हुई है और बेटियों पर अत्याचार करने वालों के लिए फांसी तक का प्रावधान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और अत्याचार को इजाज़त नहीं दी जा सकती है।...(व्यवधान) ऐसी घटनाओं में किसी एक भारतीय का भी निधन दुखद है। मानवता की मूल भावना के खिलाफ है।...(व्यवधान) जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहां राज्य सरकारें कार्रवाई कर रही हैं। मैं आज इस सदन के माध्यम से राज्य सरकारों को फिर से आग्रह करूंगा कि जो भी ऐसी हिंसा करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।...(व्यवधान) हमें 21वीं सदी के देश के सपनों को पूरा करना है। भारत माला से हाईवे का जाल पूरे देश में बिछाया जा रहा है।...(व्यवधान) सागर माला से पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट-लेड-डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। टायर-2 और टायर-3 सिटी में हवाई कनेक्टिविटी पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के शहरों में मेट्रो का व्यापक विस्तार हो, इस पर काम चल रहा है।...(व्यवधान) इस देश की हर पंचायत तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए तेज गति से काम हुआ है। देश इसका साक्षी है। गांव से लेकर बड़े शहरों तक गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बड़े बदलाव ला रही है।...(व्यवधान) पहले की सरकारों के मुकाबले हमारी सरकार की गति कहीं ज्यादा तेज है, चाहे सड़कों का निर्माण हो, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो, देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की हो, नये शिक्षा संस्थान हों, एनआईटी,

आईआईएम हो, मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि हो - कर्मचारी वही है, ब्यूरोक्रेसी हो, फाइलों का तौर-तरीका वही है, लेकिन उसके बावजूद भी यह पॉलिटीकल विल है कि जिसके कारण देश के सामर्थ्य में नई ऊर्जा भरकर हम आगे बढ़ रहे हैं।...(व्यवधान) इस देश में रोजगार को लेकर के बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। फिर एक बार सत्य को कुचलने का प्रयास, आधारहीन बातें, बिना जानकारी के गप्प चलाना - अच्छा होता, उस पर बारीकी से ध्यान देते तो देश के नौजवानों को निराश करके राजनीति करने का पाप नहीं करते।...(व्यवधान) सरकार ने सिस्टम में उपलब्ध रोजगार से संबंधित अलग-अलग आंकड़ों को देश के समक्ष हर महीने प्रस्तुत करने का निर्णय किया है। संगठित क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर में रोजगार वृद्धि को मापने का एक तरीका इम्प्लाई प्रोविडेंट फण्ड है यानी ईपीएफ में कर्मचारियों का अंशदान। सितम्बर, 2017 से लेकर मई, 2018 के नौ महीनों में लगभग 45 लाख नये सबस्क्राइबर ईपीएफ से जुड़े हैं।...(व्यवधान) इनमें से 77 परसेंट 28 वर्ष से कम उम्र के हैं। फॉर्मल सिस्टम में न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में पिछले दो महीने में 5 लाख 68 हजार से ज्यादा लोग जुड़े हैं।...(व्यवधान)

इस तरह ई.पी.एफ. और एन.पी.एस. के दो आंकड़ों को मिलाकर ही पिछले नौ महीनों में फॉर्मल सैक्टर में पचास लाख से ज्यादा लोग रोजगार में जुड़े हैं। यह संख्या पूरे वर्ष के लिए 70 लाख से भी ज्यादा होगी। इन 70 लाख कर्मियों के ई.एस.आई.सी. के आंकड़ों को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि इनमें अभी आधार लिंकिंग का काम चल रहा है।

इसके अतिरिक्त देश में कितनी ही प्रोफेशनल बॉडीज हैं, जिनमें युवा प्रोफेशनल डिग्री लेकर अपने आपको रजिस्टर्ड करते हैं और अपना काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर डाक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कास्ट एकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, इनमें एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया है और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट की स्टडी कह रही है, उन्होंने जो आंकड़े रखे हैं, उनका कहना है कि 2016-17 में लगभग 17 हजार नये चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सिस्टम में जुड़े हैं। इनमें से पांच हजार से ज्यादा लोगों ने नई कंपनियां शुरू की हैं। अगर एक चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्था में 20 लोगों को रोजगार मिलता है तो इन संस्थाओं में एक लाख

से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टर्स, डेंटल सर्जन और आयुष डाक्टर - हमारे देश में 80 हजार से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टर्स, डेंटल सर्जन और आयुष के डाक्टर शिक्षित होकर प्रति वर्ष कालेज से निकलते हैं। इनमें से अगर साठ प्रतिशत भी खुद की प्रैक्टिस करें तो प्रति डाक्टर पांच लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और यह संख्या दो लाख चालीस हजार होगी। लॉयर्स - 2017 में लगभग 80 हजार अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉयर बने। इनमें से अगर साठ प्रतिशत लोगों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की होगी और दो-तीन लोगों को रोजगार दिया होगा तो लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार उन वकीलों के माध्यम से मिला है। इन तीन प्रोफेशन में ही 2017 में छः लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं।

अब अगर इनफॉर्मल सैक्टर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सैक्टर में काफी लोगों को रोजगार मिलता है। पिछले वर्ष ट्रांसपोर्ट सैक्टर में 7 लाख 60 हजार कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री हुई। 7 लाख 60 हजार कमर्शियल गाड़ियों में से अगर 25 प्रतिशत गाड़ियों की बिक्री पुरानी गाड़ियों को बदलने के लिए मानें तो 5 लाख 70 हजार गाड़ियां सामान ढुलाई के लिए सड़क पर उतरीं और नई भी उतरीं। ऐसी एक गाड़ी पर अगर दो लोगों को भी रोजगार मिलता है तो रोजगार पाने वालों की संख्या 11 लाख 40 हजार होती है।

उसी तरह अगर हम पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री को देखें तो यह संख्या 25 लाख 40 हजार की थी। इनमें से अगर बीस प्रतिशत गाड़ियां पुरानी गाड़ियों को बदलने की मानी जाएं तो लगभग बीस लाख नई गाड़ियां सड़कों पर उतरीं। इन नई गाड़ियों में अगर केवल 25 प्रतिशत गाड़ियां भी ऐसी मानी जाएं, जो एक ड्राइवर को रोजगार देती है तो वह पांच लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।

उसी तरह से पिछले साल, हमारे यहां दो लाख 55 हज़ार ऑटोज़ की बिक्री हुई है। …(व्यवधान) इनमें से दस प्रतिशत की बिक्री अगर पुराने ऑटो को बदलने की मानी जाए तो लगभग दो लाख तीस हज़ार नए ऑटोज़ पिछले वर्ष सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि ऑटो दो शिफ्टों में चलते हैं।…(व्यवधान) दो ऑटो से तीन लोगों को रोज़गार मिलता है। …(व्यवधान) ऐसे में तीन

लाख चालीस हज़ार लोगों को नए ऑटो के जरिए रोज़गार मिला है।...(व्यवधान) अकेले ट्रांस्पोर्ट सैक्टर को इन तीन तरीकों से पिछले एक वर्ष में 20 लाख लोगों को नए अवसर मिले हैं। ...(व्यवधान) ईपीएफ, एनपीएस, प्रॉफेशनल ट्रांस्पोर्ट सैक्टर को अगर हम जोड़कर देखें तो एक करोड़ से ज्यादा लोगों को अकेले पिछले वर्ष रोज़गार मिला है। ...(व्यवधान) यह एक इण्डिपेंडेंट संस्था का सर्वे कह रहा है। ...(व्यवधान) मैं उस इण्डिपेंडेंट संस्था को कोट कर रहा हूँ। ...(व्यवधान) यह मैं सरकारी आंकड़े नहीं बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान) इसलिए मेरा आग्रह है कि कृपया कर के बिना तथ्यों के सत्य को कुचलने का प्रयास न किया जाए। ...(व्यवधान) देश को गुमराह करने का प्रयास न किया जाए। ...(व्यवधान) आज देश एक अहम पड़ाव पर है ...(व्यवधान)। आने वाले पांच वर्ष सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानियों के हैं, जिसमें 85 प्रतिशत नौजवान देश की नीयत तय करने वाले हैं।...(व्यवधान) न्यू इण्डिया, देश की नई आशा और आकांक्षाओं का आधार बनेगा।...(व्यवधान) जहां संभावनाओं, अवसरों, स्थिरता, और इनका अनंत विश्वास होगा।...(व्यवधान) जहां समाज के किसी भी वर्ग, किसी भी क्षेत्र के प्रति कोई अविश्वास नहीं होगा, कोई भेद-भाव नहीं होगा। ...(व्यवधान) इस महत्वपूर्ण समय में बदलते हुए वैश्विक परिवेश में हम सभी को साथ मिल कर चलने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, जिन लोगों ने चर्चा में भाग लिया है, मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। ...(व्यवधान) मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए एनडीए सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। ...(व्यवधान) हिन्दुस्तान में विकास की राह पर चलने वाले हर किसी के लिए जी जान से काम करने का व्रत लेकर हम आए हैं। ...(व्यवधान) मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को सन् 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण दे कर अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करने के लिए इस सदन से आग्रह करता हूँ। ...(व्यवधान)

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।

धन्यवाद।